



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]
No. 324]नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2005/अग्रहायण 29, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2005/AGRAHAYANA 29, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुल्कात संबंधी अधिसूचना (निर्णायक समीक्षा)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2005

विषय: इण्डोनेशिया, ताइवान, थाइलैण्ड तथा मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पार्श्चियली ओरिएण्टेड यार्न (पीओवाई) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के बारे में निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/9/2005- डीजीएडी- चूंकि वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 4 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं. 19/11/2000- डीजीएडी के तहत इण्डोनेशिया, ताइवान, थाइलैण्ड और मलेशिया (जिन्हें आगे सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पार्श्चियली ओरिएण्टेड यार्न (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे।

और चूंकि दिनांक 8.2.2005 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 15/2002- सी.शु. के तहत सम्बद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच में और वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद पार्श्चियली ओरिएण्टेड यार्न है जिसे पीओवाई के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण के सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 5402.42 के अंतर्गत आता है। यह पॉलिस्टर का धागा है तथा एक मध्यवर्ती है जिसे कपड़ों की बुनाई अथवा कढ़ाई हेतु उपयुक्त बनाने के लिए आगे और प्रसंस्कृत उदाहरणार्थ टैक्चरिंग अथवा झांटिंग की जाती है।

3. जांच शुरूआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए पाटनरोधी नियमों में प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करने की अपेक्षा की गई है। मैं एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज ने इंडोनेशिया, ताइवान, थाइलैण्ड और मलेशिया के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वरतु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा करने की जरूरत की पुष्टि करते हुए एक आवेदन दायर किया है और उपर्युक्त अधिसूचनाओं के तहत संबद्ध वरतु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क आगे और 5 वर्ष की अवधि तक जारी रखने तथा उसे बढ़ाने का अनुरोध किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी का मानना है कि यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क (5) के उपबंध तथा पाटनरोधी नियमों के तहत इस स्तर पर संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा करना उचित होगा।

4. शामिल देश

वर्तमान समीक्षा में शामिल देश इंडोनेशिया, ताइवान, थाइलैण्ड और मलेशिया हैं।

5. प्रक्रिया

दिनांक 4.1.2002 की अधिसूचना सं. 19/1/2000-डीजीएडी के तहत अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों तथा दिनांक 8.2.2002 की अधिसूचना सं. 15/2002-सी.शु. के तहत लगाए गए अंतिम शुल्क की समीक्षा हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट कर लेने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा इस बात की समीक्षा हेतु जांच शुरू करते हैं कि क्या सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा पाटनरोधी नियमों के अनुसार इंडोनेशिया, ताइवान, थाइलैण्ड और मलेशिया के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पीओवाई के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

इस समीक्षा में दिनांक 4.1.2002 की अधिसूचना सं. 19/1/2000-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं। मैं एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज ने मूल जांच में भी घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व किया है। प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार, आवेदक जो भारत में संबद्ध वरतु के उत्पादन के एक बड़े भाग का उत्पादन करता है, को घरेलू उद्योग मानने का प्रस्ताव करते हैं।

6. जाँच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2004 से 30 जून, 2005 तक (15 माह) की है। तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 तथा जाँच अवधि शामिल हैं।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों/उच्चायोगों के जरिए उनकी सरकारों/प्रतिनिधियों, भारत में संबंधित समझे गए आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने हेतु अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)

कमरा सं. 240, उद्योग भवन,

नई दिल्ली - 110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से जाँच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

8. समय-सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना नहीं मिलती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार, कोई हितबद्ध पक्ष अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई हितबद्ध पक्ष आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो, प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION (SUNSET REVIEW)

New Delhi, the 20th December, 2005

Subject: Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Partially Oriented Yarn (POY) originating in or exported from Indonesia, Taiwan, Thailand and Malaysia.

No. 15/9/2005-DGAD - Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), vide Notification Number 19/1/2000-DGAD dated 4th January 2002, the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Partially Oriented Yarn (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Indonesia, Taiwan, Thailand and Malaysia (hereinafter referred to as subject countries).

And whereas definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 15/2002-Customs, dated 8.2.2002.

2. Product Under Consideration

The product under consideration in the original investigation and current review is Partially Oriented Yarn generally known as POY. It falls under the custom tariff heading 5402.42 under the Indian Custom Tariff Classification. It is yarn of polyester and is an

intermediate, which is subject to further processing, for example, texturing or draw twisting, to make it suitable for weaving or knitting into fabrics.

3. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. M/s. Association of Synthetic Fibre Industries, have filed an application substantiating the need for sunset review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Indonesia, Taiwan, Thailand and Malaysia and have requested for continuation and enhancement of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years. The Designated Authority considers that the sunset review of the anti dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended and the rules made thereunder.

4. Countries Involved:

The countries involved in the present reviews are Indonesia, Taiwan, Thailand and Malaysia.

5. Procedure:

Having satisfied itself on the basis of evidence submitted by domestic industry for review of the final findings notified vide No. 19/1/2000-DGAD dated 4.1.2002 and final duty imposed by Notification No. 15/2002-Customs, dated 8.2.2002, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of Partially Oriented Yarn (POY) originating in or exported from Indonesia, Taiwan, Thailand and Malaysia, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and AD Rules.

The review covers all aspects of Notification No. 19/1/2000 -DGAD dated 4.1.2002. M/s. Association of Synthetic Fibre Industries, have represented on behalf of the domestic industry in the original

investigations also. The Authority proposes to consider the applicant, who constitutes the major proportion of the production of the subject goods in India, as domestic industry in accordance with the Rules supra.

6. Period of Investigation:

The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2004 to 30th June 2005 (15 months). However, injury analysis shall cover the years 2001-02, 2002-03, 2003-04 and POI.

7. Submission of Information:

The exporters in subject countries, their government through their Embassies/High Commissions in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit:

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

9. Inspection of Public File:

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority